ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-1* Issue-12* January-2017
Innovation The Research Concept

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका

राधाकृष्ण दुबे
एसोसिएट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
एम0डी0पी0जी0, कालेज,
प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

सारांश

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत का कृषि क्षेत्र अनेक स्तरों पर संघर्ष का दृश्य प्रस्तुत करता है। सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रूप में देखें तो देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका, किसी उद्योग और सेवा क्षेत्र की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता अर्थात् उसके सापेक्ष महत्व है। निस्सन्देह कृषि क्षेत्र समूचे देश में लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व होगा। अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार का लगभग आधा हिस्सा कृषि क्षेत्र से पैदा होता है। 70% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन प्रधानतः ग्रामीण अधोसंरचना क्षेत्रों में निवेश का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बदलते परिवेश में खेती की लागत वही है ऐसी स्थिति में किसानों की समृद्धि के लिए कृषि का व्यवसायीकरण बेहद जरूरी है। तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण कृषि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा विलुप्त हो रहा है। इस लिहाज से भी कृषि की व्यावसायिकता का महत्व बढ़ जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि का समुचित ढंग से व्यवसाय से व्यवसायीकरण तब्दील करने से इसमें उत्तरोक्तर वृद्धि होगी। जिससे ग्रामीण को गति मिलेगी।

मुख्य शब्द : भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न उत्पादन, लघु एवं सीमान्त किसान।

प्रस्तावना

भारत में खाद्यान्न उत्पादन की दिशा में 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हरित क्रान्ति की शुरुआत हुई। हरित क्रान्ति को प्रारम्भ करने का श्रेय नोबेल विजेता प्रो0 नार्मन बोरलाग को जाता है। इसके जरिए देश में असिंचित तथा सिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संथर तथा बौने बीजों का उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि करता हैं। इस क्रांति का सन्देश गाँव–गाँव तक पहुँचा कर जिस मकसद की शुरुआत की गयी थी उसमें सफलता भी मिली जिससे एक अतुल्य भारत के साथ–साथ एक ग्रामीण विकास की दशा–दिशा में परिवर्तन दिखाई पड़ा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देश्य ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका का अध्ययन करना है।

भौगोलिक अध्ययन

देश की कुल आबादी का 70% जनसंख्या गावों में गुजर बसर करती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के 85% किसान लघु एवं सीमान्त की श्रेणी में आते है इसमें खेती पर आधारित 65% ऐसे युवा है। जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। ऐसी स्थिति में सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं हर हाथ को काम दिलाने के लिए कृषि को नये आयाम तथा तकनीकी के साथ जोड़ना होगा। खाद्य सुरक्षा मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक खाद्य पदार्थों के उत्पादक किसान बंधुओं के संसाधनों की सुरक्षा नहीं की जायेगी। इसलिए आज आवश्यकता है कृषि को तकनीकी एवं संसाधन सुदृढ़ कर इसे व्यवसायिक मॉडल के तौर पर विकसित किये जाने के साथ–साथ किसानों को भी भरोसें में लेना होगा। ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में देखें तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत आधारशिला है। कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान है। जबकि 58% आबादी अपनी अजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस आधार पर हम कह सकते है कि आर्थिक–जीवन का आधार व रोजगार का प्रमुख स्रोत है वही विदेशी मुद्रा अर्जन का सशक्त माध्यम भी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दीर्घ कालीन विकास की दृष्टि से कृषि रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। गरीबी को दूर करने की रणनीति में कृषि

अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि कृषि विभिन्न क्षेत्रों के विकास दर की तुलना में गरीबी मिटाने में दुगनी प्रभावी है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कृषि क्षेत्र देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है किन्तु कृषि को घाटे का सौदा एवं बोझिल बनाकर हम बेरोजगारी और असंतोष को बढ़ावा दे रहे है।

भारत में कृषि नीति के विकास का विश्लेषण विकास प्रक्रिया में कृषि की भूमिका और खेती के विकास पर असर डालने वाले घटकों के सन्दर्भ में किया जा सकता है। गाँवों में रहने वाले निर्धन व्यक्ति को अपना जीवन स्तर सुधारने अपने क्षमताओं का दृष्टतम् उपयोग करने तथा पूरी गरिमा के साथ देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। डॉ0 मजूमदार गाँव को जीवन विधि एवं एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करते है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से 'ग्राम' वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक सम्बन्ध, हम की भावना तथा सामुदायिक भावना विशेषता पाई जाती है। ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में गाँधी जी ऐसे ग्राम समुदाय की कल्पना करते थे जो स्वयं समर्थ हो स्वशासी हो, आत्म निर्भर हो। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और लोग सद्भाव तथा सहयोग के वातावरण में रहे।

कृषि विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से ही ग्रामीण विकास के लिए आधार निर्मित होता है। कृषि मानव समाज के लिए खाद्य, वस्त्र गृह निर्माण का साधन मात्र नहीं है अपितु आवास, उद्योग व्यापार तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर को निर्धारित करने का मापदण्ड भी है। शिक्षा स्वास्थय, परिवहन, संचार आदि आधारभूत ग्रामीण सुविधाओं का समन्वय परोक्ष रूप से कृषि विकास से होता है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। जिससे विकास की एक आधारशिला तैयार होती है। राष्ट्र की प्रगति समृद्धि योजनाओं की सफलता, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, राजनैतिक स्थायित्व आदि सभी कुछ कृषि के विकास पर निर्भर है। आर्थिक प्रगति हेतु कृषि के क्षेत्र में विकसित एवं विकासशील राष्ट्र सचेष्ट है। कृषि का अभिप्राय केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादित करना ही नही वरन् पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगलों से फल फूल एवं लकड़ी का काटना जैसे कार्यों से भी है। ''कृषि को व्यापक रूप में परिभाषित किया जाता है इसके अन्तर्गत मानव की उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जिसकी सहायता से खाद्य और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए मिट्टी का उपयोग होता है। ग्रामीण विकास में कृषि विकास एवं नियोजन भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि के अन्तर्गत जीवकोपार्जन की प्रक्रिया में आखेट, पशुपालन एवं वनोत्पादों के संग्रहण की अवस्था से लेकर आज की विशिष्ट कृषि जो उच्च एवं अत्याधुनिक तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है। कृषि प्राकृतिक तथा मानवीय तत्त्वों एवं प्रक्रियाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का परिणाम है। इन तत्वों एवं प्रक्रियाओं में स्थानीय एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण इनका अर्न्तसम्बन्ध भी विभिन्न स्थलों एवं क्षेत्रों में भिन्न प्रकार का होता है।

मानव सभ्यता के विकास को जिन कारणों ने प्रभावित किया है उसमें कृषि की भूमिका सर्वविदित है। यद्यपि कहा जा सकता है कि कृषि की खोज मनुष्य ने सिर्फ इसलिए की थी कि उसको भोजन मिल सके। वैश्वीकरण और आपस में घनिष्ठता से जुड़ी दुनिया के इस दौर में ग्रामीण विकास में कृषि एक महत्वाकांक्षी सफर की शुरुआत कर चुका है। अतः ऐसा माहौल बनाना आवश्यक है जिसमें हर शख्स रचनात्मक योगदान कर सके। हर घर से बड़े रचनात्मक कार्य के लिए छोटा–छोटा योगदान शामिल हो इस तरह छोटे–छोटे अनुप्रयोगों के इस्तेमाल से ग्रामीण विकास पुष्पित पल्लवित होगा। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कृषि निर्माण को क्षेत्र लगभग सदियों से आर्थिक विकास और ग्रामीण के जीवन स्तर को बढ़ाने में मद्दगार साबित हो रहा है। ज्ञान को कृषि से जोड़ कर देखना और उसमें प्रौद्योगिकी तकनीकी के स्तम्भ को अर्थव्यवस्था में स्थापित करना भारत में अभी नया है। लेकिन कुछ वर्षों में उच्चशिक्षा में बढ़ते निजी पूंजी निवेश के कारण कृषि से उसका सम्बन्ध गहरा हुआ है। शिक्षा को कृषि से जोड़ने व उसके लिए विद्यार्थियों को अधिक सार्थक बनाने के प्रयास प्रबल हुए है।

निश्चय ही गरीबी दूर करने की रणनीति में कृषि एक महत्वपूर्ण अंग हैं। कृषि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसमें सन्देह नहीं है कि कृषि की विकास दर में वृद्धि दृष्टिगत् हो रही है जो वर्ष 1951–52 की अवधि में 2.5% थी तथा वर्तमान समय में 3.9% है। अन्य क्षेत्रों में इसकी तुलना करने पर विकास दर के मुकाबले इसकी गति धीमी रही है। लेकिन कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण दसवीं योजना के 13.9% से बढ़कर ग्यारहवीं योजना में 19% हो गया। आंशिक रूप से यह इस अवधि में कृषि के बेहतर प्रदर्शन को स्पष्ट करता है। इस प्रकार कृषि जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर पिछले दशक में एजीसीएफ में दुगने से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई सम्भवतः भारतीय कृषि में आने वाला यह सबसे बड़ा बदलाव है और यदि यह आगे भी ऐसी ही बना रह तो समय आने पर अच्छे नतीजों से सभी रूबरू हो सकेंगे। कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर अभी भी 3–4 प्रतिशत के आस पास ही धूम रही है तो वे कौन तथ्य है जो कृषि के विकास में बाधक बने हुए है? क्या कृषि में लगने वाले सभी संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिए या फिर उन संसाधनों की संरचना में किसी संसाधन की आवश्यकता है।

कृषि विकास पर असर डालने वालों घटकों को मोटे तौर पर विभिन्न वर्गों में विभक्त कर सकते है। प्राकृतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी तथा नीतिघटक आदि खेती का विकास इन सभी घटकों के परस्पर व्यवहार पर निर्भर करता है। कृषि के विकास की स्वर्णिम काल 1966–67 में हरित क्रान्ति का उद्भव एवं टेक्नोलॉजी के प्रयोग से शुरु होता है। देश ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया भारत ने खाद्य फसलों पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिये, प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार ने कृषि को नया आयाम दिया। गाँव भी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ लेकिन इसका सही स्वरूप तब दिखा जब खेती में सरकार की

भूमिका बढ़ी और अनेक कार्यक्रमों से जागरूकता में बढ़ोत्तरी हुए और आज गाँव के किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे है।

निष्कर्ष

अन्त में यह महसूस किया जा सकता है कि ग्रामीण विकास में कृषि का अपना एक विशेष योगदान है भारतीय किसान आत्मनिर्भर हुआ। श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से बाहर निकालने और खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण श्रमिकों के कौशल में निरन्तर सुधार ग्रामीण औद्योगीकरण का बढ़ावा और नवीकरण किया जाए तो और बेहतर परिणाम सामने आयेगें। उत्पादन, बाजारों एवं प्रौद्योगिकी तक किसानों की बेहतर पहुँच कायम करने के लिए ग्रामीण ढांचे के निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी भारतीय कृषि के समक्ष वर्तमान चुनौतियां कुछ अधिक जान पड़ती है। सावधानी के साथ बनायी गयी कृषि नीति ग्रामीण विकास को उत्तरोत्तर वृद्धि की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आज भारतीय किसान से ज्यादा परावलंवी दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। वह खाद, पानी, बीज, रसायनिक दवाएं, परिवहन तक दूसरों पर निर्भर है, उत्पादन और बाजार भाव के बारे में उनकी स्थिति और भी दयनीय है। आज आवश्यक है दूसरी हरित क्रान्ति का, क्यों कि हमारा किसान मेहनती है उसे सही मार्ग दर्शन एवं पर्याप्य सुविधाएं दी जाए जिससे देश की प्रगति में गाँव की भागीदारी भी उतनी हो जितनी की शहरों की है। राष्ट्र के विकास में किसान की भागीदारी भी उतनी होती है जितनी की उद्योग जगत की है। ग्रामीण विकास से ही देश की उन्नति का मानक तय किया जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Arora RC 1972, Development of Agriculture and a allied sector*
2. *Abain 1978, Agriculture Induced Innovation Technology, Institution and Development ed., Hans brinscranger. P- 323*
3. *Mishra B.N. 1994 Agricultural Managment & Planning in India. Chugh Publication Allahabad. Vol.-1*
4. *Kumar A 2003, Research Methodology in social science Satra & Sons, New Delhi*
5. *Sholly E.R. 1981, Rural Development Programme Population Decentrali- zation Policy in Development Planning, V.N. New Year.*
6. *Singh I. 1984, Agricultural Geography, New Delhi Tatamic Hill.*